की हरियाणा पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल के बाद उनके सही पाए जाने पर श्रेणी-1 के एक अधिकारी, श्रेणी-2 के एक अधिकारी श्रेणी-3 के 7 कर्मचारी और श्रेणी-4 के 2 कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। हरियाणा पुलिस ने भारतीय खाद्य निगम के 6 अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले भी दर्ज किए हैं। अन्य दो मामलों में, श्रेणी-1 के 5 अधिकारियों को विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत प्रमुख दंड के लिए चार्जशीट दी गई है। अन्य दो मामलों में श्रेणी-1 के 2 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है।

Exports of Iron-Ore by MMTC

2397. SHRI RAMDAS AGARWAL;
Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total quantity of iron-ore exported and the foreign exchange earned therefrom by the MMTC during the years 1995-96 and 1996-97 so far as compared to corresponding period of 1993-94 and 1994-95;

(b) the details of the countries (country-wise) to whom iron-ore is being exported at present including on-going negotiations at present to export iron-ore;

(c) whether Government have set any target for more export by MMTC during 1997-2000 (Ninth Plan Period) as compared to Eighth Plan Period; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) The details about total quantity of iron ore exported and the foreign exchange earned therefrom by MMTC during the period 1993-94 to 1995-96 and for the period April-October' 96 are as under:—

Year	Qty. in lakh tonnes Quantity	Value in (Rs. crores) Value
1993-94	106.06	633.60
1994-95	120.10	660.80
1995-96	111.47	688.90
1996-97 (April-October)	58.20	396.39

(b) Presently, iron ore is being mainly exported to Japan, South Korea, China, Pakistan and UAE by MMTC. During this year MMTC has signed a five year long term agreement with Japan and South Korea for export of various grades of Iron Ore. Another Long term agreement has been signed with Pakistan which is valid upto August 1997. Proposals have also been received by MMTC for entering into long term agreements with China, Thailand and Saudi Arabia.

(c) and (d) As per the Government Policy, iron ore surplus to domestic requirements is beign exported. Yearly targets (including the targets for the Ninth Plan Period) are finalised in consultation with the Ministry of Steel and MMTC. MMTC has made efforts to maximise iron ore exports during the Eighth Plan Period. The details regarding year-wise targets during the Eighth Plan period are as under:—

Year	(in
1992-93	738.00
1993-94	667.89
1994-95	584.75
1995-96	688.28
1996-97	724.20

Formation of a Dispute Settlement Panel in respect of Trips

2398. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether India had to agree to the formation of a dispute settlement panel, with respect to Trade Related Intellectual Property Rights under the World Trade Organisation;

(b) if so, whether India was averse or indifferent to the setting up of such a

pane!; if so, in what circumstances India had to yield to pressures from the developed countries; and

(c) the precise stand taken by different parties, and in what circumstances India had to yield?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (c) In pursuance of the provisions of Article 4 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) of the World Trade Organisations (WTO) and Article 64 of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, on 2 July 1996, the Government of. the United States of America had sought consultations with India regarding the alleged absence in India of either patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products or formal systems that permit the filing of patent applications for such products and that permit the grant of exclusive marketing rights in such products. The consultations were held on 27 July 1996.

The DSU provides that the complaining party may request the Dispute Settlement Body (DSB) of the WTO to establish a panel to examine the allegation if the consultations fail to settle the dispute within sixty days after the date of receipt of the request for consultations. In accordance with these provisions, on 7 November 1996 the USA requested the establishment of a panel to examine this dispute. The DSB, at its meeting held on 20 November 1996 considered this request and decided to establish a panel.

Government of India is in the process of holding consultations in order to work out appropriate measures with regard to the amendment of the Indian Patents Act 1970.

निर्यात में हेराफेरी

2399. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात से संबंधित हेराफेरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) निर्यात में हेराफेरी के लिए दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) निर्यातों के संबंध में विभिन्न प्रकार की हेरा-फेरी हो सकती है, जिनमें विदेशी मुद्रा का अप्रत्यावर्तन, बीजक में अधिक राशि दर्शाना, निर्यातों की अधिक मात्रा दर्शाने के लिए कागजात में आलसाजी अस्तित्वहीन कम्पनियां/सहायक विनिर्माताओं से निर्यात वस्तुओं की खरीद, वस्तुओं के विवरण की गलत घोषणा, निर्यातों के भार में वृद्धि करना, बोगस निर्यात आदि शामिल है। किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्यात में हेरा-फेरी के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। इन अपराधों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों और देश के अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जैसे वाणिज्य मंत्रालय/विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 जिसे अब विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 द्वारा प्रत्यास्थापित कर दिया गया है, प्रवर्तन महानिदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, वित्त मंत्रालय द्वारा कोफेपोसा, आयकर अधिनियम, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आई॰पी॰सी॰/आपराधिक दण्ड संहिता, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोफिक सब्सटांसिस अधिनियम द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इनके अलावा देश से कतिपय विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम भी हैं। इसलिए यह बताना संभव नहीं होगा कि गत तीन वर्षों के दौरान आमतौर पर निर्यात में हेराफेरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, या नहीं। जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के संबंध में निर्यात से संबंधित अतिलंघन के मामले देखने में आए हैं